



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 21, 2016/माघ 1, 1937

No. 173]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 2016/MAGHA 1, 1937

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2015

**का.आ. 197(अ).**—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 11 जून, 2015 में जिसे भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा का. आ. संख्यांक 1535(अ), तारीख 20 मई, 2015 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना के प्रकाशन पर अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित 1020.492 हेक्टर (लगभग) या 2521.63 एकड़ (लगभग) माप वाली वर्णित भूमि (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है) और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप में केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है, कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, पोस्ट बाक्स संख्या 60, जिला बिलासपुर-495006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकारी कंपनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिये रजामंद हैं;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है, कि 1020.492 हेक्टर (लगभग) या 2521.63 एकड़ (लगभग) उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकार केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने के बजाए, तारीख 11 जून, 2015 से निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात् –

1. सरकारी कंपनी, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, व्याज, नुकसानियों और वैसी ही मदों की बाबत किए गए संदायों की केन्द्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करेगी;
2. उक्त सरकारी कंपनी द्वारा शर्त (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा और ऐसे किसी अधिकरण और अधिकरण की सहायता के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे और

इसी प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में अपील आदि सभी विधिक कार्यवाहियों की बाबत उपगत, सभी व्यय भी, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे ;

3. सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो ;

4. सरकारी कंपनी को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उक्त भूमि और इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी ; और

5. सरकारी कंपनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का पालन करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित किए जाएं ।

[फा. सं. 43015/5/2013-पीआरआईडब्ल्यू-I]

सुजीत कुमार, अवर सचिव

## MINISTRY OF COAL

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2015

**S.O. 197(E).**—Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S. O. 1535(E), dated the 20<sup>th</sup> May, 2015, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 11<sup>th</sup> June, 2015, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land measuring 1020.492 hectares (approximately) or 2521.63 acres (approximately) and the all rights in or over the land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) are vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act;

And whereas the Central Government is satisfied that the South Eastern Coalfields Limited, Seepat Road, Post Box No. 60, District-Bilaspur-495006, (hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby direct that the 1020.492 hectares (approximately) or 2521.63 acres (approximately) and all rights in or over the said land so vested shall with effect from the 11<sup>th</sup> June, 2015 instead of continuing to so vest in the Central Government shall vest in the Government Company subject to the following terms and conditions, namely:—

1. The Government Company shall reimburse to the Central Government all payments made in respect of compensation, interest, damages and the like as determined under the provisions of the said Act;

2. A Tribunal shall be constituted under section 14 for the purpose of determining the amounts payable to the Central Government by the Government Company under conditions (1) and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the tribunal shall be borne by the Government Company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings including appeals for or in connection with the rights in or over the said lands so vesting shall also be borne by the Government Company;

3. The Government Company shall indemnify the Central Government or its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said lands so vested;

4. The Government Company shall have no power to transfer the said lands to any other persons without the prior approval of the Central Government; and

5. The Government Company shall abide by such direction and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said lands as and when necessary.

[F. No. 43015/ 05/ 2013-PRIW-I]

SUJEET KUMAR, Under Secy.